the level of farmers who adopt prevalent storage practices which are not sufficient to afford protection to foodgrains from rodent, insect, moisture and birds which are the main factors causing losses.

At the Government level the main agency entrusted with handling of foodgrain is Food Corporation of India. Food Corporation of India stores the foodgrains on scientific principles. Consequently the losses have been minimal during 1976-77 (0.7 per cent), 1977-78 (0.9 per cent) and 1978-79 (1.0 per cent) on the basis of quantity sold. Government is also conscious of the need to improve the storage condition at the farm level for which a phased countrywide Central Save Grain Campaign programme is under implementation for educations motivation and persuation of rural masses to adopt modern storage practices and thus reduce foodgrain losses.

गुजरात में पेय जल की कमी

5537. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में पेय जल की कमी को दूर करने के लिए विश्व बैंक द्वारा 116 करोड़ रुपये की राशि की मंजूरी किए जाने के बाद सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा योजना के लिए सहायता के रूप में कितनी राशि दी जायेगी ; और

(ग) विश्व बैंक से कितनी राशि मिलने की संभावना है और शेष व्यय को किस प्रकार पूरा किए जाने का प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री श्री भीष्म नारायण सिंह : (क) गुजरात, जलपूर्ति और मल निकास परियोजना अभी हाल ही में विश्व बैंक सहायता के लिए प्रस्तावित की गई है और अभी इसका मूल्यांकन किया जाना है ।

(ख) तथा (ग) : इस स्थिति में इसका प्रश्न ही नहीं उठता ।

Expansion of Public Sector Telephone Industries

5538. SHRIMATI GURBRINDER KAUR BRAR: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the details of expansion programme of the Public Sector Telephone Industries in the country during the next two years;

(b) whether the proposal to set up Public Sector Telephone Industries in Punjab is under consideration; and

(c) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI KARTIK ORAON): (a) To meet the growing demand of telecommunication equipment the Government have taken several steps to increase production capacities by expansion of the existing units. The most important among these are:—

(i) setting up a factory to produce 2 lakh lines per annum of indigenously developed crossbar switching equipment (ICP) at Rae Bareli Unit of ITI;

(ii) augmenting the present manufacturing capacity of 10,000 lines per annum of small electronic exchanges at Palghat Unit of ITI to 1.5 lakh lines per annum through manufacture of electronic trunk automatic exchanges, private automatic exchanges and rural auto exchanges.

(b) and (c). There are no firm proposals for setting up Public Sector

Telephone Industries in Punjab, at present. However, requests have been received for locating one of the two new Units for the manufacture of Electronic Switching equipment in Punjab. These will be considered along with other proposals, while finalizing the locations of these two Units.

फ़ैजाबाद में विश्व बैंक की सहायता से नलकूपों का लगाया जाना

5539. **श्री रामअवध**: क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित नल कूपों के लगाये जाने में काफी हेरा फेरी की जा रही है और कुछ स्थानीय अधिकारी उसमें शामिल हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) सिंचाई एक राज्य-विषय है और उत्तर प्रदेश राज्य के फैजाबाद जिले में विश्व बैंक की सहायता से लगाए जा रहे नलकूपों सहित सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है । केन्द्रीय सरकार को अभी तक इस परियोजना में किसी प्रकार की कथित हेरा-फेरी की जानकारी नहीं मिली है ।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए, यह सवाल पैदा नहीं होता ।

Central Aid for Rural Godown in Orissa

5540. SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI: Will the Minister of RURAL RECONSTRUCTION be pleased to state:

(a) whether Government have received any proposal for assistance for the construction of rural godowns from Government of Orissa; and

(b) if so, the amount asked for and the decision of the Government thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION (SHRI BALESHWAR RAM): (a) The Government of Orissa have submitted a proposal for construction of 20 rural godowns at an estimated cost of Rs. 80 lakhs.

(b) The amount of subsidy of the Central Government works out to Rs. 20 lakhs. The Project Funding Committee for Rural Godowns has approved the proposal for construction of godowns at all the 20 places.

डी० डी०ए० द्वारा गांव मादीपुर तथा शाहपुर जट के फ्लैटों के आवंटन में विलंब

5541. **श्री दौलत राम सारण** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डी० डी० ए० की जनता योजना के अधीन मादीपुर में मकान नं० 25 ए तथा 258, शाहपुर जट में मकान नं० 75, 76, 652 और मदनगीर में मकान नं० 1140 कब निर्मित किए गए थे और कब आवंटित किये गये ;

(ख) क्या इन मकानों के आवंटन में विलम्ब से डी० डी० ए० को इन पर निवेशित राशि के ऊपर ब्याज राशि को तथा किराये की हानि नहीं होती है ;